जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

ऊर्जा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित

बेहतर विद्युत आपूर्ती एवं हाई लॉस फीडर्स पर लॉस कम करने के लिए बनाई जाएगी कार्ययोजना –गंगवार

जयपुर, 15 जुलाई। ऊर्जा विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रगति के बारें में सोमवार को वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से समीक्षा करते हुए प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री नरेश पाल गंगवार ने कहा कि बेहतर विद्युत आपूर्ती एवं हाई लॉस फीडर्स पर लॉस कम करने के लिए शीघ्र ही कार्ययोजना बनाई जाएगी। वीडियो कान्फ्रेन्स में विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी. रमेश, जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ऐ.के.गुप्ता, अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री वी. एस. भाटी, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अविनाश सिंघवी, ऊर्जा विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री पीयूष सामरिया, अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल गुप्ता सहित सभी विद्युत निगमों के उत्तरदायी व प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री नरेश पाल गंगवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाई लॉस फीडर्स पर लॉस कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर उस पर कार्यवाही करे और इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के एक–एक हाई लॉस वाले फीडर का चयन कर उस पर लॉस कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है उसकी कार्ययोजना बनाकर अन्य हाई लॉस वाले फीडर्स पर भी कार्ययोजना के अनुसार कार्य किया जाए और फीडर पर कार्य के बाद लॉस कम करके उसको मॉडल फीडर बनाया जाए।

विभिन्न योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा के तहत सोमवार को आयोजित दूसरी वीडियो कान्फ्रेन्स में पिछले सोमवार को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के बारे में प्रभारी व उत्तरदायी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि जब तक हर फीडर पर मोडेम व मीटर नही होंगे और वे कम्यूनिकेट नही करगें तब तक सिस्टम से लॉस नही प्राप्त होंगे। इसके लिए जहां मोडेम व मीटर लग गए है वहां सिस्टम से और जहां नही है वहां मेनुअली फीड करके 31 जुलाई, 2019 के बाद सिस्टम से ही लॉस निकाले जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि 30 सितम्बर, 2019 तक सभी फीडरों पर यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 30 सितम्बर, 2019 के बाद एक माह से अधिक अवधि के खराब मीटर नही होने चाहिए। इसके लिए खराब मीटरों को बदलने का प्लान बनाकर उस पर तेजी से कार्य किया जाए।

कुसुम योजना के तहत जीएसएस पर उपलब्ध भूमि के चिन्हीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई और प्रत्येक जिले से 20 ऐसे सब–स्टेशनों का चयन के निर्देश दिए गए, जहां 2 मेगावाट से अधिक लोड हो और किसानों की अनुपयोगी भूमि भी उपलब्ध हो। ईआरपी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और 31 दिसम्बर, 2019 तक इस कार्य को पूरा करना है इसके बाद शत–प्रतिशत कार्य आई टी के माध्यम से हो जाएगा। केन्द्र सरकार की योजनाएं की प्रगति, विद्युत निगमों के कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए पालिसी तैयार करने, उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर करने और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तीनों डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 892/2019